विकास के कार्यों को गति देने की पहल

विकास के कार्यक्रमों को गति देने और अधिक तेजी से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनाये जाने वाले तरीके, कार्य सशक्त होकर पहल के रूप में हमारे सामने आते हैं। राज्य स्तर पर हो या जिला अथवा विकासखण्ड स्तर पर नवाचारों के प्रसार सभी को प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। इन्हीं विकासोन्मुख नवाचारों, नये प्रयासों, नई कार्यपद्धति को पहल के तहत शामिल किया गया है।

जननी सुरक्षा योजना : नये निर्देश लागू

जननी सुरक्षा योजना में हितग्राही ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों और गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान और प्रसव बाद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रावधान किये गये हैं। इस संबंध में शुल्क भी निर्धारित किया गया है। जननी सहयोगी योजना के नये पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों में बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ गर्भावस्था प्रसव और प्रसव उपरान्त अवधि में आवश्यकतानुसार आपातकालीन प्रसूति सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके अतिरिक्त बीमार नवजात शिशुओं को भी समुचित चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जायेंगी।

श्रीलंका में प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश सप्ताह का आयोजन

श्रीलंका में प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश सप्ताह आयोजित किया जायेगा। श्रीलंका यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार ने सप्ताह के आयोजन पर अपनी सहमति दी। सप्ताह के दौरान प्रदेश के सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि श्रीलंका जाकर दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देंगे।

नाम आधारित ट्रेंकिंग प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू होगी

मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नाम आधारित ट्रेंकिंग प्रणाली लागू की जायेगी। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। इस प्रणाली के तहत प्रदेश में प्रत्येक गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व से लेकर प्रसव के समय और उसके बाद पूरी तरह देखभाल करना और नवजात शिशु को समय पर टीके लगवाना सुनिश्चित करना है।

ट्रेंकिंग प्रणाली के तहत संबंधित महिला और बच्चे को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जायेगी जिसमें उसका पता, नाम, पहचान संख्या, दूरभाष क्रमांक और बच्चे की जन्मतिथि आदि शामिल रहेगी। इस प्रणाली के माध्यम से उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर भारत सरकार तक यह जानकारी होगी कि किस गांव में किस महिला या बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

आदिवासी आश्रम शालाओं में एक हजार सीटों की वृद्धि

प्रदेश में आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 930 आश्रम शालाएँ संचालित की जा रही हैं। इनमें 54 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इन आश्रम शालाओं में 492 बालकों के लिए और 438 बालिकाओं के लिए संचालित हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इस शैक्षणिक सत्र से इन आश्रम शालाओं में एक हजार नई सीटों की वृद्धि की गई है।

सैन्य परिजनों की सम्मान निधि में चार गुना वृद्धि

राज्य शासन द्वारा सैन्य परिजनों को प्रदान की जाने वाली सम्मान निधि में चार गुना वृद्धि की गई है। पहले यह राशि ढाई हजार रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

प्रत्येक नगरीय निकाय में पशु आश्रय केन्द्र

शहरी क्षेत्रों में घायल पशुओं को उचित इलाज मिल सके इसके लिये प्रत्येक नगरीय निकाय में पशु आश्रय केन्द्र खोले जायेंगे। इन आश्रय केन्द्रों का संचालन नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। पशुपालन मंत्री

श्री अजय विश्नोई ने जहांगीराबाद स्थित राज्य पशु चिकित्सालय परिसर में 25 लाख रुपये की राशि से बनने वाले पशु आश्रय केन्द्र का भूमिपूजन करने के बाद उक्त जानकारी दी।

एक हजार महिलाओं को लेदर प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा इस वर्ष आरक्षित वर्ग की एक हजार 12 महिलाओं को लेदर प्रोसेसिंग एवं लेदर गुड्स निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। यह प्रशिक्षण टाटा इन्टरनेशनल लिमिटेड देवास द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में सफल महिला प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

अब कक्षा आठ तक सतत् मूल्यांकन

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत अब शैक्षिक के साथ सह-शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को भी शामिल किया गया है। इन सबको शाला के दैनिक टाइम-टेबल में प्रावधान किया गया है तथा सब पर वार्षिक परीक्षाफल में अधिभार दिया गया है। शाला समय 7.30 घंटे होने से इसी दौरान शिक्षक प्रतिदिन उपचारात्मक शिक्षण कार्य करेगा। मासिक अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाफल का विश्लेषण कर बच्चों की कमजोरियां पता की जाएंगी और उनका निदान करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण किया जायेगा। सभी स्तर एवं सभी विषय में पर्याप्त अधिभार देने के उद्देश्य से मासिक में 80 अंक, प्रोजेक्ट में 20 अंक, अर्द्धवार्षिक में 50, वार्षिक में 100 अंक प्रति विषय रखे गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक फीडरों से विद्युत आपूर्ति

विद्युत प्रदाय के लिए फीडर सेपरेशन के कार्य को हर हाल में दिसम्बर 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर सेपरेशन का काम पूरा हो जायेगा वहां आगामी सितम्बर से बिजली की बढ़ी हुई आपूर्ति चरणों में शुरू की जायेगी।

प्रदेश में 6932 फीडर के सेपरेशन की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर तेजी से अमल किया जा रहा है। अब तक 571 फीडर का सेपरेशन किया जा चुका है जिसमें शुद्ध कृषि क्षेत्र के 191 फीडर भी शामिल हैं।

किसान कहीं से भी खरीदें कृषि यंत्र

किसानों को खेती के काम आने वाले कृषि यंत्र यथा सिंचाई उपकरण खरीदने के लिये किसी खास विक्रेता या एजेंसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान का प्रावधान है। शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय पंजीयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये यंत्र व उपकरण निर्माताओं में किसान जिस विक्रेता या निर्माता से अपनी आवश्यकता का यंत्र खरीदना चाहे उसे अनुदान की उतनी ही पात्रता होगी, भले उसने किसी भी प्रतियोगी दर पर वह उपकरण क्रय किया हो।

जेल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई

केन्द्रीय जेल भोपाल में 150 बन्दियों को तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स द्वारा इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण निर्माण उद्योग परिषद नई दिल्ली के माध्यम से दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल एवं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के डिप्लोमा कोर्स शामिल किये गये हैं। अब तक 119 बंदी तीसरा सेमेस्टर पूर्ण कर चुके हैं।

जनमित्र समाधान केन्द्र एक मार्गदर्शी पहल

ग्वालियर के जनमित्र समाधान केन्द्रों ने खासी कामयाबी हासिल की है। इस जिले में नौ महीने पहले शुरू हुए इन केन्द्रों की कार्यप्रणाली का सबूत यह है कि उनके पास इस दौरान पहुँची समस्याओं में से 92 फीसदी का उन्होंने निपटारा कर दिया है। इस कामयाबी के चलते अब इन केन्द्रों को शहरों में खोले जाने की बात भी चल पड़ी है। ग्वालियर जिले में 47 जनमित्र केन्दों को अब तक 50 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 92 प्रतिशत तक का निपटारा किया जा चुका है।

बिना हस्ताक्षर वाले शिकायत पत्रों पर भी मानव अधिकार आयोग संज्ञान लेगा

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी ने कहा है कि यदि प्रदेश का कोई बंदी मानव अधिकार से संबंधित अपनी समस्या का आवेदन बिना दस्तखत के भी भेजता है तो आयोग उस पर संज्ञान लेकर जांच करेगा।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए वाहनों पर चमकीली पट्टी

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से परिवहन मंत्रालय ने परिवहन वाहनों पर चमकीली पट्टी लगाने के आदेश पारित किए हैं। प्रदेश के समस्त आर.टी.ओ. कार्यालयों को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर राजमार्ग पर चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों पर जैसे टेम्पो, आटो, ट्रक, यात्री बस, ट्रेक्टर ट्राली और भारी ट्राले पर चमकीली पट्टी लगाना अनिवार्य किया है। निर्देशों के अनुसार अब वाहनों के आगे की तरफ सफेद रेडियम

पट्टी, दोनों तरफ साइड में पीली पट्टी और पीछे की तरफ लाल पट्टी लगाई जायेगी। इस प्रक्रिया से पट्टी लगी होने वाले वाहनों से दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आयेगी।

परिवहन विभाग ने प्राइवेट वाहनों के मालिकों से भी आग्रह किया है कि वह अपनी गाड़ियों पर उक्त तीनों रंगों की पट्टियां लगायें ताकि वह भी दुर्घटना से सुरक्षित रह सकें। परिवहन विभाग में फिटनेस के लिए अब आने वाले सभी वाहनों पर यह तीनों रंगों की पट्टियां लगी होना अनिवार्य होंगी।

साठ लाख बालिकाओं को मिलेंगी दो जोड़ी ड्रेस

प्रदेश में स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में तेजी से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप इस वर्ष छात्राओं को निःशुल्क गणवेश, साईकिल एवं अन्य सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें निर्धारित समय सीमा से वितरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में कक्षा- एक से आठवीं तक की लगभग साठ लाख बालिकाओं को दो जोड़ गणवेश निःशुल्क प्रदाय किये जा रहे हैं। गणवेश में प्रयुक्त होने वाले कपड़े की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने हेतु विगत वर्ष की अपेक्षा इस साल विशेष प्रयास किये गये हैं।

गेहूँ की जगह मिलेगा आटा

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के खासकर निम्न और मध्यम आयवर्गीय परिवारों को गेहूँ की बजाय अब गुणवत्तापूर्ण आटा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस योजना को 15 अगस्त से प्रदेश के सारे संभागों के शहरी क्षेत्रों में लागू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एपीएल और बीपीएल कार्डधारी उपभोक्ताओं को मिल रहे तयशुदा गेहूँ के अलावा इस आटे का विक्रय किया जाएगा। आटे में जरूरी पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाएगा। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि बाजार की अपेक्षा यह आटा सस्ता और वाजिब दाम पर मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण आटे के सुविधाजनक 10-10 किलोग्राम के पैकेट तैयार किये जायेंगे और इतनी ही मात्रा प्रति कार्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने तय किया है कि इस आटे को लेने में कहीं किसी को दिक्कत पेश न आये इसलिये इसका विक्रय शहरी क्षेत्रों की सभी उचित मूल्य दुकानों और सहकारी उपभोक्ता भण्डारों से किया जाएगा।

पचास हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन

राज्य शासन ने छब्बीस जिलों के पचास हाई स्कूलों का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया है। इन स्कूलों को वर्ष 2010-11 से उन्नत कर प्रारंभ करने की अनुमति जारी की गई है।

जबलपुर में मेडिकल विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में मेडिकल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है।

नीदरलैण्ड के सहयोग से बनेगी नगरों की विकास योजना

प्रदेश के चुनिन्दा महानगरों में अधोसंरचना विकास और नागरिक सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नीदरलैण्ड के रोटेस्डम शहर की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था आई.एच.एस. के साथ सहयोग की योजना तैयार कर रहा है। उक्त संस्था शहरी अधोसंरचना एवं शहरी आवास योजना के क्षेत्र की विशेषज्ञ मानी जाती है।

खण्डवा में कुपोषित बच्चों को गोद लेंगे शासकीय सेवक

खण्डवा जिले का सरकारी अमला कुपोषण के खात्मे के लिये असरकारी ढंग से काम करेगा। इसके लिये हाल में जिले के सभी शासकीय सेवकों ने एक-एक कुपोषित बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश में मदद करने का संकल्प लिया है। जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के अनुसार कुपोषित ऐसे बच्चों की सूची सभी कार्यालय प्रमुखों को दी जा रही है। वन, स्कूल, राजस्व सहित सभी विभागों के मैदानी अमले के कर्मचारी एक-एक बच्चे को नामजद गोद लेंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में लगभग 4,000 कम वजन के बच्चों को चिन्हित किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले में कार्यरत शासकीय अमले की संख्या 6,678 है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश नियम समिति गठित

उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रवेश नियमों की समीक्षा करते हुए आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं। यह समिति प्रवेश के लिए राज्य और राज्य के बाहर के विद्यार्थियों का प्रतिशत निर्धारित करने के संबंध में सुझाव देने के साथ ही अन्य विषयों पर अनुशंसाएँ देगी। समिति में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और ग्वालियर विश्वविद्यालय के कुलसचिव सदस्य रहेंगे। समिति विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उन विषयों की निरन्तरता के संबंध में सुझाव देगी जिनमें मध्यप्रदेश के छात्र उपलब्ध नहीं होते।